

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 27 Sep, 2024

Edition: International | Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 3 : पर्यावरण	इडुक्की गांव में जंगली हाथियों को मानव बस्तियों से दूर भगाने के लिए विशेष पहल
Page 04 Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति	बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की पुनर्विचार याचिका खारिज की
Page 10 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में तूफान आने की आशंका
Page 11 Syllabus : GS 1 – इतिहास	क्रांतिकारी विचारक और विचारक भगत सिंह का जीवन
समाचार में घटनाएँ	जीवितपुत्रिका महोत्सव
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति और शासन	भारत की पेंशन प्रणाली पर पुनर्विचार करने का अवसर

वन विभाग ने इडुक्की के मरयूर वन प्रभाग के अंतर्गत कंथल्लूर गांव में उत्पात मचाने वाले जंगली हाथियों को भगाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की।

Special initiative to drive away wild elephants from human habitations in Idukki village

The Hindu Bureau
IDUKKI

The Forest Department started a special initiative to drive away wild elephants that wreak havoc in Kanthallur village under the Marayur forest division in Idukki. According to the department officials, an 84-member team began the initiative on Thursday morning to drive away the elephants from human habitations in Kanthallur panchayat to Chinnar Wildlife Sanctuary.

Marayur divisional forest officer P.J. Shuhaib said the drive will continue on Friday. "The department aims to drive away problematic elephants from farm-



A wild tusker roaming in Kanthallur panchayat in Idukki on Thursday. SPECIAL ARRANGEMENT

lands," said the official.

Kanthallur panchayat president P.T. Thankachen expressed satisfaction with the department's special drive addressing man-animal conflict in the panchayat. "As many as 18 wild elephants were camping in

various parts of the panchayat, which made it hard for the people to engage in farming activities," he said.

M.R. Kumaravel, a farmer in Kanthallur, said that for the past three months, wild elephants have been camping on the farmlands.

- ➡ विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 84 सदस्यों वाली टीम ने गुरुवार सुबह हाथियों को कंथल्लूर पंचायत में मानव बस्तियों से चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य की ओर खदेड़ने की पहल शुरू की।
- ➡ मरयूर प्रभागीय वन अधिकारी पी.जे. शुहाब ने कहा कि अभियान शुक्रवार को भी जारी रहेगा। अधिकारी ने कहा, "विभाग का लक्ष्य समस्याग्रस्त हाथियों को खेतों से खदेड़ना है।"
- ➡ कंथल्लूर पंचायत के अध्यक्ष पी.टी. थंकाचेन ने पंचायत में मानव-पशु संघर्ष को संबोधित करने के लिए विभाग के विशेष अभियान पर संतोष व्यक्त किया।
- ➡ उन्होंने कहा, "पंचायत के विभिन्न हिस्सों में 18 जंगली हाथी डेरा डाले हुए हैं, जिससे लोगों के लिए खेती-बाड़ी के कामों में शामिल होना मुश्किल हो गया है।"
- ➡ कंथल्लूर के किसान एम.आर. कुमारवेल ने कहा कि पिछले तीन महीनों से जंगली हाथी खेतों पर डेरा डाले हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी के अपने फैसले की समीक्षा करने की गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था।

- ▶ गुजरात सरकार ने जनवरी के फैसले में अदालत द्वारा की गई कुछ "प्रतिकूल" टिप्पणियों का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि राज्य के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए थीं। हालांकि, अदालत ने समीक्षा याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और इसे खारिज कर दिया।

समाचार के बारे में

- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करने वाले 8 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।
- ▶ जनवरी के फैसले में गुजरात पर एक दोषी राधेश्याम शाह के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि मई 2022 में छूट देने का आदेश धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाकर हासिल किया गया था।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के आदेश के खिलाफ जल्दी समीक्षा दायर न करने के लिए गुजरात की भी आलोचना की, जिससे आगे के मुकदमे से बचा जा सकता था।

गुजरात सरकार का रुख

- ▶ अपनी समीक्षा याचिका में, गुजरात ने तर्क दिया कि वह अपनी 1992 की छूट नीति के तहत छूट आवेदन पर निर्णय लेने के लिए केवल 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन कर रहा था, हालांकि उसने लगातार कहा कि निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र ही उपयुक्त प्राधिकारी है।
- ▶ राज्य ने अदालत के "सत्ता के हड़पने" के आरोप को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उसे समीक्षा याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिलकिस बानो ने खुद ऐसा किया था, लेकिन दिसंबर 2022 में उसकी समीक्षा खारिज कर दी गई थी।
- ▶ राज्य ने आगे तर्क दिया कि वह किसी भी धोखाधड़ी में शामिल नहीं था।

Bilkis Bano verdict: SC dismisses review petition by Gujarat

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Thursday found no "error apparent on the face of the record" or merit in a petition filed by the Gujarat government to review adverse remarks made against it by the top court in a January 8 judgment, which quashed the premature release of 11 men sentenced to life imprisonment for the gang rape of Bilkis Bano and the murder of her family during the 2002 riots in the State.

The review was decided by a Bench of Justices B.V. Nagarathna and Ujjal Bhuyan.

The State of Gujarat had remitted the life sentence of the 11 convicts and released them from jail in August 2022.

The Supreme Court's January 8 verdict had passed scathing remarks about the alacrity shown by the Gujarat government to "usurp"

Maharashtra's authority in deciding on the remission. The trial in the case was held in Maharashtra, which was the competent authority to decide the remission applications of the 11 convicts.

The Gujarat government had found some of the observations in the January 8 judgment "extreme", including that the State had "acted in tandem and was complicit with [one of the] accused". It had argued in the review plea that such remarks in the judgment was not only highly unwarranted but had caused serious prejudice to the State.

"Having carefully gone through the review petitions, the order under challenge and the papers annexed therewith, we are satisfied that there is no error apparent on the face of the record or any merit in the review petitions, warranting reconsideration of the order impugned," the Supreme Court said.

छूट क्या है?

➡ के बारे में

- छूट एक कम अवधि पर सजा की पूरी समाप्ति है।
- छूट फरलो और पैरोल दोनों से अलग है क्योंकि यह जेल जीवन से विराम के विपरीत सजा में कमी है।

➡ संवैधानिक प्रावधान

- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ, स्थगित, राहत या छूट दे सकते हैं या निलंबित, माफ या कम कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल सजा को माफ, स्थगित, राहत या छूट दे सकते हैं या निलंबित, माफ या कम कर सकते हैं।

➡ छूट की वैधानिक शक्ति

- डंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में जेल की सजा में छूट का भी प्रावधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेल राज्य का विषय है।
- सीआरपीसी की धारा 432 के तहत, 'उपयुक्त सरकार' किसी सजा को पूरी तरह या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या बिना किसी शर्त के निलंबित या माफ कर सकती है।
- सीआरपीसी की धारा 433 के तहत, किसी भी सजा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम सजा में बदला जा सकता है।
- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे कैदियों को जेल की अवधि पूरी होने से पहले उन्हें रिहा करने का आदेश दे सकें।

➡ CrPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है।

- ➡ बीएनएसएस 2023 का अध्याय XXXIV निम्नलिखित धाराओं के तहत कुछ मामलों में छूट या कम करने की शक्तियों से संबंधित है:
 - धारा 473 - सजा को निलंबित या माफ करने की शक्ति।
 - केंद्र सरकार के पास ऐसे मामलों में ऐसा करने की शक्ति है जहां सजा किसी ऐसे कानून के खिलाफ अपराध के लिए है जो संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत आता है।
 - अन्य मामलों में, जिस राज्य में अपराधी को सजा सुनाई जाती है, वहां की सरकार के पास ऐसा करने की शक्ति है।
 - धारा 474 - सजा को कम करने की शक्ति। उपयुक्त सरकार अपराधी की सहमति के बिना किसी भी सजा को किसी अन्य सजा में बदल सकती है।
 - धारा 475 - कुछ मामलों में छूट या कम करने की शक्तियों पर प्रतिबंध।
 - धारा 477 - कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्य करना।

➡ छूट देते समय पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश

- 'लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ' (2000) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच आधार निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर छूट पर विचार किया जाता है:
 - क्या अपराध एक व्यक्तिगत अपराध है जो समाज को प्रभावित नहीं करता है;
 - क्या भविष्य में अपराध के दोहराए जाने की संभावना है;
 - क्या दोषी ने अपराध करने की क्षमता खो दी है;

- क्या दोषी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है; और
- दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- साथ ही, आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी कम से कम 14 साल जेल में रहने के बाद छूट पाने के हकदार हैं।

➡ बिलकिस बानो केस क्या है?

- 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के बाद, बिकनी बानो और उनके परिवार पर लोगों के एक समूह ने हमला किया था।
- बिलकिस के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई।
- उसका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, जिसने CBI को जांच का आदेश दिया।
- लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण, मुकदमा गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इन लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए।
- जनवरी 2008 में, मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
- इन दोषियों की रिहाई
- 2022 में, राधेश्याम शाह नामक एक दोषी ने अपनी आजीवन कारावास की 15 साल और चार महीने की सजा पूरी करने के बाद, जल्दी रिहाई के लिए SC का रुख किया।
- मई 2022 में, SC ने इस मामले को गुजरात सरकार को सौंप दिया।
- इसने गुजरात सरकार से राज्य की 1992 की छूट नीति के अनुसार, शाह की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करने को कहा।
- 15 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया।
- हालांकि, इस फैसले ने जनता में भारी आक्रोश पैदा कर दिया और विपक्षी सांसदों की याचिकाओं को बढ़ावा दिया।

➡ बिलकिस बानो द्वारा समीक्षा याचिका

- बिलकिस बानो ने 2022 में गुजरात सरकार के उस फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी का फैसला
- बिलकिस बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका के जवाब में, शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 जनवरी के फैसले की मुख्य बातें

- गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं थी, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चल रहा था। छूट आदेश में सक्षमता का अभाव है।
- अपराधियों को केवल उस राज्य द्वारा रिहा किया जा सकता है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

Daily News Analysis

- पीठ ने यह भी माना कि 13 मई, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था।
- गुजरात सरकार को 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी, जिसमें कहा गया था कि वे सक्षम सरकार नहीं हैं।
- मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के खिलाफ कड़ी आलोचना की।
- मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि छूट के मुद्दे पर दो राज्य सरकारों का समवर्ती क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता।
- किसी अपराधी की समय से पहले रिहाई पर उस राज्य में लागू नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जहां अपराध किया गया था
- इसलिए, इन दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार की छूट नीति लागू की गई।
- परिणामों की परवाह किए बिना कानून के शासन को संरक्षित किया जाना चाहिए।

हाल के वर्षों में, पूर्वी एशिया के समुद्री क्षेत्र में शक्ति संघर्ष में वृद्धि देखी गई है, जिसमें चीन ने पूर्वी चीन सागर में जापान-नियंत्रित सेनकाकू/दियाओयू द्वीपों पर दावा किया है, जिससे बार-बार तनाव उत्पन्न हो रहा है।

Storms brewing in East, South China seas

What has led to a flare-up in tensions in recent times? Why does China see its claims over the seas as defensive actions? Why do the regional countries consider it provocative? Why is the U.S. drawn into the conflict? What lies ahead?

EXPLAINER

Sankalp Gurjar

The story so far:

In the last few years, maritime East Asia has become an arena for intensified power politics. The East China Sea borders China, Taiwan, Japan, and South Korea. China asserts that the Senkaku/Diaoyu islands, located in the East China Sea and under Japanese control, belong to Beijing. There have been multiple crises over these islands in the past. The South China Sea lies between China, Taiwan and five Southeast Asian countries – Vietnam, Malaysia, Brunei, the Philippines, and Indonesia – and has emerged as one of the most important flashpoints in the Indo-Pacific. China has been aggressively pushing its claims in the South China Sea.

Why are the seas important to China?

China views the East and South China Seas through the prism of sovereignty, territorial integrity, and national security. China's Defence White Paper, issued in 2019, declares, "South China Sea islands and Diaoyu Islands are inalienable parts of the Chinese territory." In responding to the criticism regarding China's activities, it asserts that "China exercises its national sovereignty to build infrastructure and deploy necessary defensive capabilities on the islands and reefs in the South China Sea, and to conduct patrols in the waters of Diaoyu Islands in the East China Sea." What China perceives as its defensive actions are considered offensive and provocative by the regional countries surrounding the East and South China Seas.

What is the significance of the seas?

The key maritime trade routes in East Asia pass through these two seas. Taiwan Strait is a critical maritime choke point. The region is home to undersea cables that are important for the global digital economy. As per the U.S. Energy Information Administration, in 2023, 10 billion barrels of petroleum and petroleum products and 6.7 trillion cubic feet of liquefied natural gas passed through the South China Sea. It is also home to vast reserves of untapped oil and natural gas.

What is China doing in the region?

China has been aggressively pushing its territorial claims in both seas in two ways: by building defence-related infrastructure such as ports, military installations, airstrips, and artificial islands and by pushing back against the claims of regional countries. In the East China Sea, China vehemently contested Japanese claims and, both countries found themselves embroiled in multiple crises, the most notable being the arrest of a Chinese captain of a fishing boat in 2010 and Japan's nationalisation of the Senkaku islands in 2012. These crises saw both countries taking maximalist positions. China had imposed a ban on the export of rare earth minerals to Japan. In the last few years, there has been a slight easing of tensions over the issue regarding the Senkaku/Diaoyu islands. As per the Japan Coast Guard data, 2023 saw the highest level of activity by the Chinese Coast Guard in the contiguous zone of the Senkaku. Owing to China's assertive foreign policy, its relationship with South Korea, Taiwan and Japan has deteriorated rapidly.

Meanwhile, the South China Sea has



Tensions rise: Members of the Philippine Coast Guard on alert as a Chinese Coast Guard vessel blocks their way to a resupply mission at Second Thomas Shoal in the South China Sea, on March 5, 2024. REUTERS



growing continuously. China's navy is also the largest naval force in the world by numbers. Therefore, the South China Sea is seeing the ever-growing projection of Chinese power. For asserting its claims, China has deployed a Coast Guard and maritime militia. The tactics include dangerous and aggressive manoeuvres at sea, harassing resupply missions, ramming vessels, collisions, and using water cannons and military-grade lasers, etc. These tactics are known as 'grey zone' operations, which fall short of war but are designed to alter the status quo.

China has been actively pushing its claims in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Philippines. Since 2022, tensions between China and the Philippines have been rising due to a significant increase in the frequency of such incidents. In June-July 2024, multiple incidents of clashes occurred. The Second Thomas Shoal and Sabina Shoal have been the focus of China's recent

contention. China aims to drive a wedge between the U.S. and its treaty partners in East Asia. Chinese Coast Guard ships are considerably heavier and larger in terms of tonnage compared with Coast Guard vessels of other countries. For example, the Chinese vessel CCG 5901 (541 feet long and displaces 12,000 tons) is three times larger than the main ships of the U.S. Coast Guard. Hence, China's frequent ramming of the Philippines' vessels is dangerous and risky. There is a chance of miscalculation.

In July, China conducted naval exercises with Russia in the South China Sea to demonstrate the support that it enjoys over it while projecting its claims. China's claims in the South China Sea lack a legal basis, according to a permanent court of arbitration ruling in 2016. However, China has rejected that ruling.

What has been the response from regional countries?

regional countries trying to catch up with China. For example, by 2027, Japan wants to double its defence expenditure. The Philippines too is ramping up its defence capabilities and, among others, has acquired the anti-ship, BrahMos missiles from India.

Second, regional countries are responding to China's activities at sea. From 2016 to 2022, Under President Rodrigo Duterte, the Philippines sought to minimise the friction between Manila and Beijing. Since 2022, the Philippines has been pushing back and publicising these incidents. The change in policy was crafted by the new President Ferdinand Marcos Jr. As a result, the frequency of incidents has gone up. Regional countries are engaged in a battle of narratives as well. They are deploying tools such as public diplomacy. The Philippines has been filming the behaviour of Chinese vessels and is releasing it through social media. The Philippines has also taken international journalists along with its resupply missions in the West Philippine Sea. The shaping of perceptions has become a key battleground.

Third, the Philippines, Japan and South Korea are treaty allies of the U.S. and are strengthening their defence relationship with it. The U.S. and the Philippines have enhanced their cooperation in the South China Sea to "historic levels" and expanded cooperation in domains such as base access, training and joint exercises. They are working with Australia and Japan in "a complex multilateral maritime cooperative activity." It is dubbed as the "Squad." According to U.S. Secretary of Defence Lloyd Austin, the U.S.' commitment to the security of Japan is "ironclad" and includes the Senkaku islands as well. The U.S., Japan, and South Korea are deepening their trilateral cooperation. For the first time in history, the Defence Ministers of the three countries met in Japan in July 2024. In view of aggressive Chinese maritime activities, the press statement noted that these three countries "strongly oppose any unilateral attempts to change the status quo in the waters of the Indo-Pacific." They also "stressed the importance of fully respecting international law including the freedom of navigation and overflight."

Despite the efforts at bolstering the U.S.' alliances in the Indo-Pacific, concerns remain about American credibility and the impact of the U.S.' domestic politics on its external security commitments. There is also a debate about whether the U.S. engagement in

THE GIST

China asserts sovereignty over the East China Sea, particularly the Senkaku/Diaoyu islands, which are controlled by Japan, and pushes its claims in the South China Sea, leading to heightened tensions with several Southeast Asian nations.

The East and South China Seas are vital maritime trade routes, housing essential undersea cables and significant reserves of oil and natural gas, making them critical for regional and global economies.

China is expanding its military presence by building artificial islands, military infrastructure, and aggressive maritime tactics, which include harassing vessels from neighbouring countries.

In reaction to China's assertiveness, countries like Japan and the Philippines are increasing their defence capabilities while shifting policies to confront Chinese actions.

पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव क्या है?

► पूर्वी चीन सागर: मुख्य मुद्दा सेनकाकू/दियाओयू द्वीप समूह के इर्द-गिर्द घूमता है, जिस पर चीन और जापान दोनों का दावा है।

Daily News Analysis

- चीनी मछली पकड़ने वाली नाव के कप्तान की गिरफ्तारी और 2012 में जापान द्वारा द्वीपों के राष्ट्रीयकरण जैसी घटनाओं के कारण तनाव बढ़ गया है। इस क्षेत्र में चीनी तटरक्षक बल की घुसपैठ भी देखी जाती है।
- ➔ दक्षिण चीन सागर: कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और नौसैनिक अभ्यास जैसे आक्रामक कार्यों द्वारा समर्थित अधिकांश क्षेत्र पर चीन के दावों ने वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ तनाव बढ़ा दिया है।
- चीन के "नाइन-डैश लाइन" दावों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा खारिज कर दिया गया है, लेकिन बीजिंग इन दावों को आगे बढ़ाना जारी रखता है।
- ➔ यूएसए संदर्भ: अमेरिका जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के साथ सुरक्षा गठबंधन बनाए रखता है, सैन्य समर्थन प्रदान करता है। इन सहयोगियों के बीच संयुक्त अभ्यास और सहयोग में वृद्धि हुई है।
- "स्क्वाड" (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस) का गठन चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए समन्वय को उजागर करता है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय कारक इन क्षेत्रों में तूफान के पैटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं?

- ➔ तूफान के पैटर्न और बढ़ते समुद्र: यह क्षेत्र चरम मौसम की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, जिसमें टाइफून भी शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक तीव्र और लगातार होते जा रहे हैं।
- समुद्र के बढ़ते स्तर और बदलते तूफान के पैटर्न तटीय समुदायों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालते हैं।
- ➔ द्वीपों का क्षरण: चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण तटीय क्षरण को तेज कर रहा है और प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर रहा है, जो स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा सैन्य गतिविधियों के क्या निहितार्थ हैं?

- ➔ बढ़ता सैन्यीकरण: चीन ने हवाई पट्टियों, बंदरगाहों और अन्य रक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित अपनी सैन्य उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है।
- चीनी तटरक्षक और समुद्री मिलिशिया अन्य दावेदार राज्यों के जहाजों को परेशान करने में सक्रिय रहे हैं, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में।
- ➔ अमेरिकी नौसेना को चुनौती दें: चीन की सैन्य गतिविधियों को इंडो-पैसिफिक में अमेरिकी नौसेना के वर्चस्व को चुनौती देने की उसकी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
- ➔ इस रणनीति में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, समुद्र के नीचे केबल और ऊर्जा भंडार को नियंत्रित करना भी शामिल है।

स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्थाएँ कैसे प्रभावित होती हैं?

- ➔ आर्थिक व्यवधान: दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों, विशेष रूप से विवादित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के आसपास, ने मछली पकड़ने पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।
- ➔ समुद्री व्यापार: यह क्षेत्र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का घर है, जिसके माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति सहित वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है।
- ➔ इन जल क्षेत्रों में किसी भी संघर्ष या नाकाबंदी का गंभीर वैश्विक आर्थिक प्रभाव होगा।
- ➔ पर्यटन पर प्रभाव: बढ़ता सैन्यीकरण और तनाव तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

आगे का रास्ता:

Daily News Analysis

- ➡ समुद्री साझेदारी को मजबूत करना: भारत को एक स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) और आसियान जैसे मंचों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में अपनी रणनीतिक समुद्री साझेदारी को बढ़ाना चाहिए।
- ➡ आर्थिक और अवसंरचना कूटनीति: भारत SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) जैसी पहलों का लाभ उठा सकता है और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अवसंरचना, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण परियोजनाओं में निवेश करके अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ा सकता है।



28 सितंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी “भगत सिंह” की 117वीं जयंती है।



Rich legacy: His writings must be read widely, this perhaps would be a better tribute to Bhagat Singh's life as a revolutionary than propagandism or empty political posturing. FILE PHOTO

A life in revolution: Bhagat Singh, a radical thinker and ideologue

A look back at the works of a revolutionary who was martyred in the fight for freedom; erudite, and a polyglot, he filled his short and tumultuous life writing on many subjects, from communalism and inequality to religion and faith, words which have a chilling contemporary relevance

Prathmesh Kher

In our age and clime, a radical worldview is often simplified. As if an entire ideology could be reduced to a haiku, and the worth of a man reduced to mere sloganeering. Whether it is Gandhi, Ambedkar, Bose, Savarkar, or Nehru, all are victims of this malaise; as if those who existed in the past serve merely the political interests of the present. One such figure in history is Bhagat Singh. On his birth anniversary, we take a look back at some of the works of the thinker and ideologue.

Literary references

Bhagat Singh was able to communicate in Urdu, Punjabi, Hindi, and English, and was familiar with the fundamentals of Sanskrit.

In one of his earliest pieces in 1923, *The Problem of Punjab's Language and Script*, a 16-year-old Singh lucidly explains the distinction between the Gurmukhi script and the Punjabi language, and how a language is suffused with influences far beyond man-made borders.

Singh's jail notebook and letters also reflect the eclecticism of his literary diet.

In *Vishwa Prem* (Universal Love), published in November 1924, Singh declares “*Visvabandhuta* (Universal Brotherhood)! For me the greatest meaning of this word is equality and nothing else. None will need to cry for bread when hungry... There would be peace without penal codes.”

Singh extols Rana Pratap, Mazzini, Gandhiji, Lenin, Washington, Savarkar, Tilak, and MacSwiney as models for the youth, and harkens to Brutus in Roman history, and Krishna in the Mahabharata in the article.

By 1928, the stark realities of the Indian situation were more apparent to

the young Singh.

In the article *Communal Riots and their Solution*, Singh comes down hard on the journalists of his day, writing, “These people arouse public sentiment by writing bold headlines in the newspapers against one or the other and compel people to start fighting with one another... riots started in many locations just because of the fact that local newspapers had written articles that stoked passions.”

“The actual duty of newspapers is to educate, to liberate people from narrow-mindedness, eradicate fundamentalism, to help in creating a sense of fraternity among people, and build a common nationalism in India, but these papers behaved in a manner entirely antithetical to their duties,” he says.

Students and politics

“We are hearing a wide clamouring that students should not take part in political work,” Singh writes in a July 1928 article, *Students and Politics*, explaining how the then Punjab government required aspiring collegiates to “sign off on an undertaking that they will not take part in political activities.” Singh says that an education which will “only equip them for clerical jobs” would be “worthless.” “They should study, but at the same time they should acquire the knowledge of politics too, and when the need arises they should jump into the fray and sacrifice their lives for the nation,” Singh states.

In his June 1928 article, *The Problem of Untouchability*, Singh exhorts the “so-called untouchables, the real sustainers of life” to remember that they “were the backbone of Guru Gobind Singh's army. Shivaji was able to achieve all he did with your participation and it made him forever shine in history,” Singh

urges them to “unite to stand on your own feet and challenge the existing order of society.”

Declaring the idea that “since someone is born in a poor sweeper's family, he shall continue cleaning toilets all his life” as “utter nonsense”, Singh stokes the depressed classes to “start a revolution from a social agitation.” Singh reminds the untouchables that they “are the pillars of the nation and its core strength. Awake, O sleeping lions! Rebel, raise the banner of revolt.”

In a December 1929 article, *What is Revolution?*, Singh explains, “The spirit of revolution should always permeate the soul of humanity so that reactionary forces may not accumulate to check its eternal onward march. Old order should change, always and ever, yielding place to new, so that one ‘good’ order may not corrupt the world. It is in this sense that we raise the shout ‘Long Live Revolution.’”

In a three-part piece titled, *What is Anarchism?*, published in 1928, Singh reflects, “Anarchists are against God and religion to begin with because they feel this is the root of mental slavery. And then they are against the State because it is the root of physical slavery. They say that motivating people with the temptation of heaven, fear of hell, or with the iron hand of law is the wrong approach and it is also an insult to a superior being like a human.”

In his 1931 *Letter to Young Political Workers*, Singh writes, “According to our definition of the term, revolution means the complete overthrow of the existing social order and its replacement with the socialist order... the state, the government machinery is just a weapon in the hands of the ruling class to further and safeguard its interest. We want to snatch it, and handle it, to utilise it for the consummation of our ideal, i.e., social

reconstruction on a new, i.e., Marxist, basis.”

Challenging faith

As an atheist and a materialist, Singh had thought organised religion to be an impediment to the freedom struggle in particular and to social progress in general. “We can see the mountain of religion standing in our path,” Singh writes in an April 1928 article, *Religion and our Freedom Struggle*. “... a clash between people could be instigated with the loud recitation of Koranic verses and Vedic mantras. The question is then, why should we not do away with all this once and for all?” he asks.

In *Why I am an Atheist*, Singh declares, “Any man who stands for progress has to criticise, disbelieve and challenge every item of the old faith. Item by item, he has to reason out every nook and corner of the prevailing faith... An individual who claims to be a realist has to challenge all of ancient faith.”

In an April 1929 letter to his compatriot Sukhdev, Singh writes about how the emotion of “love” can elevate a human life. Writing of Mazzini in the aftermath of the failed rebellion, Singh says, “He could have either gone mad or committed suicide, but with a letter from his beloved, he became not only as strong as the others, but stronger than everybody else... The character of a person is always elevated by love; it never shows one in a bad light provided that the love is true love. True love can never be created. It wells up by itself when no one can predict.”

Bhagat Singh wrote and worked extensively in his short and tumultuous life. His writings must be read widely – this perhaps would be a better tribute to Singh's life as a revolutionary than propagandism or empty political posturing.

► भगत सिंह कौन थे?

जन्म	28 सितम्बर, 1907; बंगा, पंजाब (अब पाकिस्तान में)
------	--

Daily News Analysis

परिवार	उनका परिवार उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था; उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे।
संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> • हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (1924) • हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (1928) • नौजवान भारत सभा (1926)
क्रांतिकारी कार्य	<ul style="list-style-type: none"> • लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने और गलती से जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या करके लाहौर षडयंत्र केस (1928) में अहम भूमिका निभाई • दमनकारी ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल, 1929 को बी.के. दत्त के साथ केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका।
विचारधाराएँ और सिद्धांत	<ul style="list-style-type: none"> • मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधाराओं की वकालत की • अपने निबंध 'मैं नास्तिक क्यों हूँ' में धर्म को खारिज किया • तर्कवाद, समानता और न्याय पर जोर दिया।
गिरफ्तारी और मुकदमा	<ul style="list-style-type: none"> • 1929 में केंद्रीय विधान सभा में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया; बाद में लाहौर षडयंत्र मामले (जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया। • जिन्ना ने 1929 में अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति देने वाले विधेयक का विरोध किया, और केंद्रीय विधानसभा में एक जोरदार भाषण दिया।
निष्पादन	<ul style="list-style-type: none"> • 23 मार्च, 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी दे दी गई। • नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जेल में भगत सिंह से मुलाकात की।
साहित्यिक रचनाएँ	<ul style="list-style-type: none"> • भगत सिंह उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में पारंगत थे और संस्कृत से भी परिचित थे। • उनकी जेल नोटबुक में कार्ल मार्क्स, थॉमस जेफरसन, मार्क ट्वेन और अन्य विचारकों का संदर्भ था, जो उनकी बौद्धिक विविधता को दर्शाता है। • 17 साल की उम्र में, उन्होंने विश्व प्रेम (सार्वभौमिक प्रेम) लिखा, जिसमें सार्वभौमिक भाईचारे और समानता की वकालत की गई। • उन्होंने उत्पीड़ित वर्गों से सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया और अपने लेखन में क्रांति के दर्शन के बारे में बात की, जैसे कि क्रांति क्या है? (1929)। • अपनी श्रृंखला अराजकतावाद क्या है? में उन्होंने संगठित धर्म और

Daily News Analysis

राज्य को मानसिक और शारीरिक गुलामी के रूप में वर्णित किया।

- उन्होंने 1929 में सुखदेव को लिखे पत्र में प्रेम की शक्ति के बारे में लिखा, जिसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक ताकत में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया।



Event In News : Jivitputrika Festival

- ➡ हाल ही में जीवित्पुत्रिका त्योहार के दौरान बिहार के कई जिलों में नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते समय 37 बच्चों सहित कम से कम 46 लोग डूब गए।



जीवित्पुत्रिका उत्सव के बारे में:

- ➡ जीवित्पुत्रिका या जितिया व्रत, एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल सहित भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मनाया जाता है।
- ➡ यह उन माताओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने बच्चों की भलाई, लंबी आयु और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं।
- ➡ यह त्योहार तीन दिनों तक चलता है, जिसमें मुख्य अनुष्ठान सख्त 'निर्जला' उपवास होता है, जिसका अर्थ है कि उपवास के दौरान पानी नहीं पिया जाता है।
- ➡ यह व्रत एक माँ की भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति माना जाता है, इस विश्वास के साथ कि यह उसके बच्चों पर दिव्य आशीर्वाद लाएगा।

Daily News Analysis

- ➡ यह त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से राजा जीमूतवाहन की कहानी पर आधारित है, जिनके दूसरों के कल्याण के लिए बलिदान को इस दौरान याद किया जाता है।
- ➡ यह उत्सव नहाय-खाय से शुरू होता है, जहाँ माताएँ शुद्ध स्नान करती हैं और पौष्टिक भोजन करती हैं।
- ➡ दूसरे दिन कठोर उपवास अनुष्ठान होता है, और त्योहार तीसरे दिन पारण के साथ समाप्त होता है, जहाँ भोजन के साथ उपवास तोड़ा जाता है।



Page : 08 Editorial Analysis

An opportunity to rethink India's pension system

The pension system in India has undergone a significant transformation over the years with three major schemes, the Old Pension Scheme (OPS), New Pension Scheme (NPS), and the proposed Unified Pension Scheme (UPS), marking the different phases of government policy. Each scheme impacts retirees in different ways, with the OPS often being viewed as a more secure system compared to the NPS, which ties retirement funds to volatile market conditions. As the world witnesses a retreat from neoliberal policies, the debate around welfarism is being reignited. In this context, the UPS requires considerable rectification to ensure that it serves the interests of retirees effectively.

A shift with greater individual risk

The OPS, prevalent before 2004, guaranteed a defined benefit pension to government employees. In this scheme, the pension amount was fixed and determined by the last drawn salary, and the government was solely responsible for disbursing the pensions. The OPS provided stability and ensured that retirees were insulated from any financial market risks. The reliance on a fixed percentage of the last drawn salary for pensions meant that employees could plan their retirements with a sense of financial security, knowing that they would have a guaranteed income stream throughout their post-retirement years. The OPS reflected the government's commitment to social security by excluding the market from the equation and offering guaranteed pensions.

In 2004, the Government of India replaced the OPS with the New Pension Scheme (NPS). Here, the shift was from a defined-benefit model to a defined-contribution model, wherein employee and the government contributed towards a pension fund, which was then invested in financial markets. The pension payout under the NPS is linked to the performance of these investments, meaning retirees' incomes are now subject to the fluctuations of market forces.

The shift from OPS to NPS represents the neoliberal tendency to reduce state involvement



T.T. Sreekumar

Professor, The English and Foreign Languages University, Hyderabad

in welfare provisions and transfer risk to individuals. The NPS left retirees vulnerable to market volatility, effectively placing their futures at the mercy of speculative market conditions. The NPS has drawn criticism because the security once provided by the state under OPS has been eroded. During periods of economic downturn, retirees may face reduced returns, undermining their financial stability.

This market-driven pension model has also fuelled wider concerns about the commercialisation of public welfare programmes and the weakening of the state's social responsibility.

A return to welfarism

Globally, the era of neoliberalism that dominated economic policy for the past few decades is showing signs of a retreat. The 2008 financial crisis exposed the risks associated with excessive market reliance, leading to calls for stronger social safety nets and a return to welfarism. The COVID-19 pandemic further amplified these demands, as governments worldwide were compelled to intervene in unprecedented ways to protect the health and livelihoods of their citizens. India, too, is experiencing a similar shift, with demands for the return of state-backed welfare provisions.

The UPS, as proposed by the Narendra Modi government, emerges in this context as an attempt to provide universal pensions while balancing state involvement and market participation.

While the U-turn of the Modi government, as pointed out by the Opposition, aims to address the issues raised by the NPS, the UPS is still in its nascent stages and requires significant rectification before it can be seen as a viable alternative to the NPS. Critics have already pointed out that the UPS promises retirement payouts but offers reduced returns compared to the OPS and exposes retirees to the risks of uncertain market-based assets. The requirement of 25 years of service for a full pension is a disadvantage for those who join late, while potential underfunding raises concerns about

future pension delays or corpus depletion.

Moreover, the scheme only covers Union government employees, excluding many public sector workers such as teachers, and may disincentivise further pay commissions. One of the critical aspects of the UPS that needs attention is the need for greater state intervention to ensure that retirees are not left vulnerable to market forces. While the UPS offers a universal framework, its structure should incorporate safeguards against market fluctuations, possibly by providing a minimum guaranteed pension similar to the OPS.

Issue of government contribution

Another area that needs reform is the level of government contribution. The UPS hybrid model would not completely mitigate risks associated with market reliance and may fail to offer a balanced pension system. Further, ensuring the inclusivity of the UPS across all sectors, including informal labour, is critical. India's vast informal workforce currently lacks adequate pension coverage. The UPS must broaden its scope to provide pension security to all citizens, and not just to government employees, aligning with the broader return of welfarism that is gaining momentum globally.

The comparison of the OPS, the NPS and the UPS illustrates the tension between state-backed welfare and market-driven policies in India's pension system. While the OPS provided a stable and predictable pension income, the NPS shifted retirees' financial futures into the volatile realm of market investments, creating uncertainties and vulnerabilities. The retreat of neoliberalism and the return to welfarism worldwide, although on a limited scale or even notionally, provide an opportunity to rethink India's pension system and strike a better balance between state responsibility and market participation. The UPS, if properly restructured, could become an important tool in protecting the financial security of retirees and addressing the shortcomings of the NPS, ensuring that India's retirees are not left to the mercy of market forces but are supported by a robust welfare system.

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति एवं शासन

UPSC Mains Practice Question भारत में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से नई पेंशन योजना (एनपीएस) में परिवर्तन के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तथा कल्याणवाद की ओर वैश्विक बदलाव के संदर्भ में सेवानिवृत्त लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की क्षमता का मूल्यांकन करें। (250 w /15 m)

संदर्भ:

- ▶ भारत में पेंशन प्रणाली जांच के दायरे में है, क्योंकि प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में चर्चा जोर पकड़ रही है। यह वैश्विक स्तर पर नवउदारवादी नीतियों से पीछे हटने और कल्याणवाद के लिए फिर से उठने वाले आह्वान के बीच हुआ है, जो सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रभावी पेंशन सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

परिचय

- ▶ भारत में पेंशन प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में तीन प्रमुख योजनाओं, पुरानी पेंशन योजना (OPS), नई पेंशन योजना (NPS) और प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो सरकारी नीति के विभिन्न चरणों को चिह्नित करता है।
- ▶ प्रत्येक योजना सेवानिवृत्त लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है, जिसमें OPS को अक्सर NPS की तुलना में अधिक सुरक्षित प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो सेवानिवृत्ति निधि को अस्थिर बाजार स्थितियों से बांधता है। जैसे-जैसे दुनिया नवउदारवादी नीतियों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, कल्याणवाद के बारे में बहस फिर से शुरू हो रही है।
- ▶ इस संदर्भ में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सेवानिवृत्त लोगों के हितों की प्रभावी रूप से सेवा करे, UPS में काफी सुधार की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत जोखिम के साथ बदलाव पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बारे में

- 2004 से पहले प्रचलित OPS ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित लाभ पेंशन की गारंटी दी।
- इस योजना में, पेंशन राशि तय की गई थी और अंतिम आहरित वेतन द्वारा निर्धारित की गई थी।
- पेंशन वितरित करने के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार थी।
- ▶ वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा: OPS ने स्थिरता प्रदान की और सुनिश्चित किया कि सेवानिवृत्त लोग किसी भी वित्तीय बाजार जोखिम से सुरक्षित रहें।
- पेंशन के लिए अंतिम आहरित वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर निर्भरता का मतलब था कि कर्मचारी वित्तीय सुरक्षा की भावना के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बना सकते थे।
- सेवानिवृत्त लोगों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में एक गारंटीकृत आय धारा का आश्वासन दिया गया था।
- ▶ सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता: OPS ने सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया।
- बाजार को समीकरण से बाहर करके, इस योजना ने सेवानिवृत्त लोगों को गारंटीकृत पेंशन की पेशकश की।
- ▶ OPS से NPS में बदलाव: 2004 में, भारत सरकार ने OPS को नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया।
- यह बदलाव परिभाषित-लाभ मॉडल से परिभाषित-योगदान मॉडल की ओर हुआ, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों ने पेंशन फंड में योगदान दिया।

इसके बाद इस फंड को वित्तीय बाजारों में निवेश किया गया।

- ▶ बाजार से जुड़ा पेंशन भुगतान: एनपीएस के तहत पेंशन भुगतान इन निवेशों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।
- सेवानिवृत्त लोगों की आय अब बाजार की ताकतों के उतार-चढ़ाव के अधीन है।
- ▶ नवउदारवादी बदलाव और जोखिम हस्तांतरण: ओपीएस से एनपीएस में बदलाव कल्याणकारी प्रावधानों में राज्य की भागीदारी को कम करने की नवउदारवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है।

जोखिम को व्यक्तियों पर स्थानांतरित करने से सेवानिवृत्त लोग बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो गए हैं

- ➡ सेवानिवृत्त लोगों का भविष्य अब सट्टा बाजार स्थितियों की दया पर है।
- ➡ एनपीएस की आलोचना: एनपीएस ने ओपीएस के तहत राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को खत्म करने के लिए आलोचना की है। आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान, सेवानिवृत्त लोगों को कम रिटर्न का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता कम हो सकती है।
- ➡ व्यावसायीकरण और सामाजिक जिम्मेदारी पर चिंताएँ: बाजार संचालित पेंशन मॉडल ने सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यावसायीकरण के बारे में चिंताओं को बढ़ावा दिया है। यह राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी के कमजोर होने के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

कल्याणवाद की वापसी

- ➡ विश्व स्तर पर, पिछले कुछ दशकों से आर्थिक नीति पर हावी रहने वाले नवउदारवाद का युग पीछे हटने के संकेत दे रहा है।
- ➡ 2008 के वित्तीय संकट ने अत्यधिक बाजार निर्भरता से जुड़े जोखिमों को उजागर किया, जिससे मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल और कल्याणवाद की वापसी की मांग उठी।
- ➡ कोविड-19 महामारी ने इन मांगों को और बढ़ा दिया, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और आजीविका की रक्षा के लिए अभूतपूर्व तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- ➡ भारत भी इसी तरह के बदलाव का अनुभव कर रहा है, जिसमें राज्य समर्थित कल्याण प्रावधानों की वापसी की मांग की जा रही है।

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत

- ➡ नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित UPS, इस संदर्भ में राज्य की भागीदारी और बाजार की भागीदारी को संतुलित करते हुए सार्वभौमिक पेंशन प्रदान करने के प्रयास के रूप में उभर कर सामने आता है।

यूपीएस की आलोचना और चुनौतियाँ

- ➡ जैसा कि विपक्ष ने कहा है, मोदी सरकार का यू-टर्न एनपीएस द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से है, यूपीएस अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और इसे एनपीएस के व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखे जाने से पहले महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।
- ➡ आलोचकों ने पहले ही बताया है कि यूपीएस सेवानिवृत्ति भुगतान का वादा करता है, लेकिन ओपीएस की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करता है और सेवानिवृत्त लोगों को अनिश्चित बाजार-आधारित परिसंपत्तियों के जोखिमों के लिए उजागर करता है।
- ➡ पूर्ण पेंशन के लिए 25 साल की सेवा की आवश्यकता उन लोगों के लिए एक नुकसान है जो देर से शामिल होते हैं, जबकि संभावित कम वित्तपोषण भविष्य में पेंशन में देरी या कॉर्पस की कमी के बारे में चिंता पैदा करता है।
- ➡ इसके अलावा, यह योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करती है, जिसमें शिक्षकों जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल नहीं हैं, और यह आगे के वेतन आयोगों को हतोत्साहित कर सकता है।

Daily News Analysis

- ➡ अधिक राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता: यूपीएस के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है अधिक राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त लोग बाजार की ताकतों के सामने कमजोर न पड़ें।
- ➡ जबकि यूपीएस एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करता है, इसकी संरचना में बाजार में उतार-चढ़ाव के खिलाफ सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए, संभवतः ओपीएस के समान न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करके।

सरकारी योगदान का मुद्दा

- ➡ सरकारी योगदान में सुधार की आवश्यकता: एक अन्य क्षेत्र जिसमें सुधार की आवश्यकता है, वह है सरकारी योगदान का स्तर।
 - यूपीएस हाइब्रिड मॉडल बाजार निर्भरता से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह से कम नहीं करेगा और एक संतुलित पेंशन प्रणाली प्रदान करने में विफल हो सकता है।
- ➡ सभी क्षेत्रों में समावेशिता: इसके अलावा, अनौपचारिक श्रम सहित सभी क्षेत्रों में यूपीएस की समावेशिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
 - भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल में वर्तमान में पर्याप्त पेंशन कवरेज का अभाव है।
 - यूपीएस को सभी नागरिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाना चाहिए, न कि केवल सरकारी कर्मचारियों को, जो वैश्विक स्तर पर गति प्राप्त कर रहे कल्याणवाद की व्यापक वापसी के साथ संरेखित हो।

निष्कर्ष

- ➡ ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की तुलना भारत की पेंशन प्रणाली में राज्य समर्थित कल्याण और बाजार संचालित नीतियों के बीच तनाव को दर्शाती है। जबकि ओपीएस ने एक स्थिर और अनुमानित पेंशन आय प्रदान की, एनपीएस ने सेवानिवृत्त लोगों के वित्तीय भविष्य को बाजार निवेश के अस्थिर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, जिससे अनिश्चितताएं और कमजोरियां पैदा हुईं।
- ➡ नवउदारवाद का पीछे हटना और दुनिया भर में कल्याणवाद की वापसी, हालांकि सीमित पैमाने पर या यहां तक कि सैद्धांतिक रूप से, भारत की पेंशन प्रणाली पर पुनर्विचार करने और राज्य की जिम्मेदारी और बाजार की भागीदारी के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- ➡ यूपीएस, अगर ठीक से पुनर्गठित किया जाता है, तो सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करने और एनपीएस की कमियों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के सेवानिवृत्त लोगों को बाजार की ताकतों की दया पर नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उन्हें एक मजबूत कल्याण प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाता है।

It's about quality